

नोएडा के बाद लखनऊ-कानपुर तकनीक के उभरते केंद्र

आईटी-आईटीईएस सेक्टर में यूपी ने की बड़ी तरक्की, 5600 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव धरातल पर उतारे

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। पिछले आठ वर्षों में आईटी-आईटीईएस सेक्टर में प्रदेश ने बड़ी तरक्की की है। यूपी का नोएडा न सिर्फ देश के बड़े आईटी हब के रूप में स्थापित है, बल्कि लखनऊ-कानपुर जैसे शहर भी इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।

प्रदेश में आईटी-आईटीईएस के क्षेत्र में कुल 27 हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारा जा चुका है।

डिलीवरी की रिपोर्ट में आईटी-आईटीईएस सेक्टर में प्रदेश के योगदान का जिक्र है। रिपोर्ट के

प्रदेश में आईटी सेक्टर को उद्योग का दर्जा

राज्य में आईटी-आईटीईएस के क्षेत्र के विकास की गति को और तेज करने के लिए योगी सरकार ने कई लक्षित नीतिगत उपाय किए हैं। प्रदेश में आईटी सेक्टर को उद्योग का दर्जा दिया गया है, जिससे आईटी इकाइयों को कम बिजली दरों और औद्योगिक भूमि वैकों तक पहुंच का लाभ मिल रहा है। राज्य स्टार्टअप इकोसिस्टम भी चला रहा है, जिसमें अब 14 हजार से अधिक पंजीकृत स्टार्टअप शामिल हैं। योगी सरकार ने मेडटेक, ब्लॉकचेन, टेलीकॉम, एआई, ड्रोन व एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में 70 इनक्यूबेटर व सात उत्कृष्टता केंद्रों को मान्यता दी है।

अनुसार, आईटी-आईटीईएस क्षेत्र वर्तमान में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में 3.2% का योगदान देता है। अनुमान है कि आने वाले वर्षों में यह 5% से अधिक होगा। राज्य से आईटी

निर्यात 75,000 करोड़ से अधिक रहा है। वित्त वर्ष 2023-24 में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पावर्स ऑफ इंडिया (एसटीपीआई) के माध्यम से निर्यात ने 43,000 करोड़ से अधिक का योगदान दिया।

पिछले कुछ वर्षों में नोएडा ने खुद को एक प्रमुख प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में स्थापित किया है। नोएडा में माइक्रोसॉफ्ट का अत्याधुनिक रिसर्च सेंटर इसका प्रमाण है। यहां 15 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। 15 एकड़ में फैला यह कैपस अमेरिका के बाहर माइक्रोसॉफ्ट का सबसे बड़ा कैपस है। वहीं, नैसकॉम ने लखनऊ और कानपुर को उभरते प्रौद्योगिकी केंद्रों के रूप में मान्यता दी है। लखनऊ में 258 एकड़ में फैली आईटी सिटी का विकास हो रहा है।

आईबीएम भी लखनऊ में अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर लैब खोलने जा रही है, जो एआई समेत सॉफ्टवेयर और आईटी

उत्तर प्रदेश में एक साल में सबसे ज्यादा 3318 नई फैक्ट्रियां पंजीकृत हुईं

लखनऊ। भारत सरकार द्वारा संचालित वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण के ताजा आंकड़ों में वित्त वर्ष 2024-25 उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 3318 फैक्ट्रियों का पंजीकरण हुआ है। यह आंकड़ा वर्ष 2020-21 (1484) के मुकाबले दोगुने से ज्यादा है। ये अब तक की सबसे बड़ी वृद्धि में से एक है। खास बात यह है कि इन पंजीकृत इकाइयों में से 460 फैक्ट्रियां ऐसी हैं, जहां सी से अधिक कर्मचारी कार्यरत होंगे। यह संकेत है कि बड़े औद्योगिक निवेश के लिए यूपी प्रमुख गंतव्य बन चुका है। औद्योगिक सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) के स्तर पर भी यूपी ने बड़ी छलांग लगाई है। वर्ष 2022-23 में राज्य का जीवीए बढ़कर 1.3 लाख करोड़ रुपये हो गया है, जो देश के कुल औद्योगिक जीवीए में 6.1% की भागीदारी सुनिश्चित करता है। उद्योगों के लिए बेहतर कानून व्यवस्था, सिंगल विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम आदि ने निवेशकों का विश्वास मजबूत किया है। ब्यूरो

सॉल्यूशंस के क्षेत्र में काम कर न पटल पर भी ग्लोबल लीडर के तौर सिर्फ देश-प्रदेश, बल्कि वैश्विक पर स्थापित करेगा।